RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 160
दि. 09.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के आगमन पर स्वागत किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत की उनकी पहली ऐतिहासिक यात्रा के

आगमन पर हार्दिक स्वागत किया है। उनके साथ ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वह भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंपा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेट्रो लाइन-3 का भी किया शुभारंभ

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही, उन्होंने मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और देश के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का भी शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं के उद्घाटन से शहर की स्थिति एक वैश्विक विकास और अवसर केंद्र के रूप में और मजबूत होगी ह्व

शुरूआत में 2 करोड़ यात्रियों को मिलेगी सेवा

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण पर 19,647 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और यह 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हवाई अड्डा सालाना 2 करोड़ यात्रियों और 5 लाख टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। अंतिम चरण में, यह हवाई अड्डा 9 करोड़ यात्रियों

और 32.5 लाख टन कार्गो की क्षमता वाला एक विश्व स्तरीय केंद्र बन जाएगा।

नवी मुंबई हवाई अड्डे से जुड़ी खास बातें:

1. भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डाः हवाई अड्डे पर वाहन पार्किंग स्लॉट पूर्व-बुकिंग, ऑनलाइन बैगेज ड्रॉप और इमिग्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, पूरी तरह से ऑटोमेटेड और अक्-सक्षम टर्मिनल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा।

2. प्रारंभिक क्षमताः 1,160 हेक्टेयर में फैले हवाई अड्डे की शुरूआती स्थिति में एक रनवे और टर्मिनल के जरिए सालाना 2 करोड़ यात्री सेवा ले सकेंगे। पूरी क्षमता पर यह चार टर्मिनल और दो रनवे के जरिए सालाना 15.5 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा।

3. लागत और रोजगारः इस हवाई अड्डे का निर्माण ₹19,650 करोड़ में हुआ है। यहां से एविएशन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।

4. एयरलाइन योजनाएंः इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर जैसी कई एयरलाइंस ने पहले ही देश के विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट संचालन की योजना साझा कर दी है।

5. वाणिज्यिक संचालनः दिसंबर से वाणिज्यिक संचालन शुरू होगा, जिसमें 40% अंतरराष्ट्रीय यातायात होगा, जो धीरे-धीरे बढ़कर 75% तक पहुंच जाएगा।

अयोध्या में बृहस्पति कुंड का लोकार्पण और संतों की प्रतिमा का हुआ अनावरण, सीएम-वित्तमंत्री रहे मौजूद

(जीएनएस)।

रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। आज यहां केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेढ़ी बाजार चौराहे स्थित बृहस्पति कुंड का भव्य लोकार्पण किया साथ ही दोनों नेताओं ने दक्षिण भारतीय संतों की प्रतिमाओं का अनावरण किया।

लोकार्पण व अनावरण कार्यक्रम के बाद दक्षिण भारत से आये कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। सीएम योगी व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन प्रतिमाओं का अनावरण किया उनमें संत श्री पुरंदर दास, श्री त्यागराज और श्री अरुणाचल कवि की प्रतिमा है।

रामनगरी अयोध्या आज फिर एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नगर में बने बृहस्पति कुंड का लोकार्पण करने के साथ ही परिसर में बनी दक्षिण भारत के संतों की प्रतिमाओं का अनावरण कर दिया।

बृहस्पति कुंड पर दक्षिण भारत के तीन प्रख्यात संतों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जिनका अनावरण केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री ने किया है। बृहस्पति कुंड रामनगरी के 108 पौराणिक स्थलों में से एक है इस कुंड की महत्ता विभिन्न शास्त्रों में बताई गई है।

राम मंदिर परिसर के यात्री सुविधा केंद्र में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इसमें अयोध्या की परंपरा, भक्ति और दक्षिण भारतीय संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। इसको लेकर पुलिस-प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अयोध्या पहुंच गई हैं। इस मौके पर यूपी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आम जनमानस, बिना चिकित्सक के पर्चे एवं बिना बिल के किसी भी प्रकार के कफ सिरप का खरीद फरोख्त न करें

सहायक आयुक्त (औषधि) आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सेक्टर सी अलीगंज लखनऊ पत्र एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्यों में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मृत्यु की घटनाएँ सामने आई हैं। इस विषय में राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से अवगत कराया गया है कि M/s Sresan Pharmaceutical, Manufacturer No-787, Bangalore Highways, Sunguvachatram (Mathura) Distt-Kanchipuram-602106 द्वारा निर्मित COLDRIF SYRUP, Batch No- SR&13, Mfg- Date: MAY 2025, Exp- Date: APR 2027 ¸fZa Diethylene Glycol का अपमिश्रण पाया गया है। Diethylene Glycol एक अत्यंत हानिकारक व विषैला रसायन है, जिसका अपमिश्रण मानव स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। इस गंभीर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में निम्न निर्देश जारी किए गये है-

COLDRIF SYRUP A±fUf M/s Sresan Pharmaceutical द्वारा निर्मित किसी भी अन्य कफ सिरप को औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों एवं सरकारी / गैर-सरकारी अस्पतालों में चिन्हित करें। उसका नमूना संकलित कर, अभिरक्षा में लेकर विक्रय पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया गया एवं लिये गये कफ सीरप के सभी नमूनों को लखनऊ प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु तत्काल प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं कार्यक्षेत्र में स्थित निर्माणशालाओं / समस्त थोक / फुटकर औषधि विक्रेताओं से कफ सीरप का नमूना संकलित करके जॉच व विश्लेषण हेतु लखनऊ प्रयोगशाला प्रेषित करे तथा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत तत्काल यथावश्यक नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों व सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में संलग्न पत्र में उल्लिखित औषधि अथवा मे० खेसन फार्मास्युटिकल द्वारा विनिर्मित अन्य कोई भी कफ सिरप पाये जाने पर उसका नमूना संकलित करते हुए अभिरक्षा में लेने व रोकने की कार्यवाही करते हुए कफ सिरप के सभी नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु तत्काल प्रेषित करायें

उक्त निदेशों के क्रम में श्री सुनील कुमार रावत, औषधि निरीक्षक प्रयागराज द्वारा दिनांक 06.10.2025 को सी. एम.एस.डी स्टोर तेलियरगंज से 02 कफ सिरप का औषधि नमूना संग्रहीत किया गया एवं 02 औषधि नमूनें थोक मार्केट (लीडर रोड) से सीज करते हुए अग्रिम कार्यवाही की गयी। दिनांक 07.10.2025 को श्री संतोष कुमार पटेल, औषधि निरीक्षक प्रयागराज द्वारा 02 कफ सिरप का औषधि नमूना संग्रहीत किया गया एवं नियमानुसार प्रेषित किया गया। दिनांक 08.10.2025 को श्री संतोष कुमार पटेल, औषधि निरीक्षक प्रयागराज द्वारा 03 कफ सिरप का औषधि नमूना संग्रहीत किये गये एवं श्री सुनील कुमार रावत, औषधि निरीक्षक प्रयागराज द्वारा 02 कफ सिरप का औषधि नमूना संग्रहीत किया गया है जिनको जॉच हेतु राजकीय विष्लेशक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया है। उपरोक्त नमूने राजकीय भण्डारण कक्ष, जन औषधि केन्द्र, थोक औषधि विक्रेताओं की फर्मो से संग्रहीत किये गये है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

दीप प्रज्वलन के साथ देवा मेला 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य शुभारंभ

- डीएम की धर्मपत्नी ने किया उद्घाटन, सुर-ताल और भावनाओं से सजी सांस्कृतिक संध्या

(जीएनएस)।

बाराबंकी, 08 अक्टूबर। विश्व प्रसिद्ध देवा मेला एवं प्रदर्शनी 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ बुधवार को देवा मेला ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मेला समिति अध्यक्ष श्री शशांक त्रिपाठी तथा उनकी धर्मपत्नी शैलजा त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अरुण कुमार सिंह, एडीएम (न्यायिक) राजकुमार सिंह, एसडीएम आनंद कुमार तिवारी, सीएमओ डॉ. अवधेश कुमार यादव, बीएसए संतोष कुमार देव पांडेय, तथा मेला समिति के सदस्यगण चौधरी तालिब नजीब, राय स्वरेश्वर बली, फव्वाद किदवई, संदीप सिन्हा, सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

(संगीत की बहार से गूंजा ऑडिटोरियम)

उद्घाटन के पश्चात कार्यक्रमों की शुरूआत बहार सुगम संगीत प्रभाग के निर्देशक प्रभात नारायण दीक्षित तथा उनके छात्र-छात्राओं की गणेश वंदना और स्वरचित कव्वाली 'ये मेरे वारिस पिया ले लिया मेरा जिया'से हुई। इसके बाद गिटार प्रशिक्षक कार्तिकेय कैलाश दीक्षित के निर्देशन में तैयार 'शिवराजे म्यूजिकल बैंड'ने बॉलीवुड मिक्स पर धमाकेदार प्रस्तुतियां दीं। युवा कलाकारों की इस प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर गया।

(स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल)

देवा मेला के मंच पर शहर के विभिन्न विद्यालयों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। बालाजी का बचपन स्कूल के बच्चों ने शिक्षिकाओं सविता कौर, अल्पना कौर, रिचा अग्निहोत्री, शगुन रस्तोगी, सना हुसैन, अलीशा जैदी के निर्देशन में गणेश वंदना प्रस्तुत की, जिसने शुभारंभ को और भी भव्य बना दिया। वहीं बालाजी एकेडमी के विद्यार्थियों ने शिक्षिकाओं अना खान, समन सिद्दीकी, नारायणी श्रीवास्तव, हादिया अकरम, श्रेया जायसवाल, और शिक्षकों अहमर शहबाज, पीयूष मौर्य के निर्देशन में 'पहलगाम अटैक'पर आधारित देशभक्ति नृत्य-नाटिका प्रस्तुत कर दर्शकों की तालियां बटोरीं।

(अरुणोदय पब्लिक स्कूल की सामाजिक प्रस्तुति ने छोड़ी गहरी छाप)

देवा मेला उद्घाटन अवसर पर अरुणोदय पब्लिक स्कूल, बाराबंकी के विद्यार्थियों ने 'कोलकाता रेप केस'पर आधारित एक भावनात्मक नाट्य प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों की संवेदनाओं को झकझोर दिया। इस नाट्य प्रस्तुति का निर्देशन शिक्षिकाओं शाज़िया अल्वी, अंजित (रिंकू), तुलाराम (राणा), माया सिंह और मंतशा ने किया, जबकि बाल कलाकार अंशिका, काव्या और अन्य बच्चों के उत्कृष्ट अभिनय को सराहना मिली।

(सकारात्मक संदेश के साथ हुआ सांस्कृतिक संध्या का समापन)

सांस्कृतिक संध्या का समापन तालियों की गूंज और प्रसन्नता के माहौल में हुआ।

लोकसभा अध्यक्ष 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी) के लिए बारबाडोस पहुंचे, जो 5 से 12 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित होगा

(जीएनएस)।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, 5 से 12 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन (सीपीसी) में भाग लेने के लिए बारबाडोस के ब्रिजटाउन पहुंचे हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, राष्ट्रमंडल भर के सांसदों के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, सुशासन को बढ़ावा देने और संसदीय कूटनीति और सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है।

सम्मेलन के आगमन पर, अध्यक्ष श्री ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में

राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश, सांसद श्री अनुराग शर्मा और सीपीए कार्यकारी समिति के सदस्य, डॉ. डी. पुरंदेश्वरी, सांसद और सीडब्ल्यूपी संचालन समिति के सदस्य, डॉ. के. सुधाकर, सांसद, श्रीमती रेखा शर्मा, सांसद, डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े, सांसद श्री उत्पल कुमार सिंह, लोक सभा के महासचिव और राज्य सभा के महासचिव श्री पीसी मोदी शामिल हैं।

सम्मेलन के एक भाग के रूप में, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला आज एक प्रमुख कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे जिसका विषय है: "प्रौद्योगिकी का लाभः डिजिटल परिवर्तनों के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा और डिजिटल विभाजन से निपटारा।"

श्री बिरला 68वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की आम सभा को "राष्ट्रमंडलः एक वैश्विक साझेदार" विषय पर संबोधित करेंगे, जिसमें वे लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी शासन, संसदीय पारदर्शिता और वैश्विक संसदीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालेंगे।

सम्मेलन के दौरान समसामयिक मुद्दों पर सात विषयगत कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। भारत के 24 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के विधायी सदनों के 36 पीठासीन अधिकारियों सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य इन कार्यशालाओं में भाग लेंगे।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा भारत—कतर रणनीतिक आर्थिक भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए कतर का दौरा

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत—कतर आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग आयोग की बैठक के लिए दोहा, कतर का सरकारी दौरा किया। श्री गोयल ने दोहा में कतर देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महामहिम शेख फैजल बिन थानी बिन फैसल अल थानी के साथ आयोग की

सह—अध्यक्षता की। यह फरवरी 2025 में कतर के अमीर की भारत यात्रा के दौरान पूर्ववर्ती व्यापार एवं वाणिज्य के संयुक्त कार्य समूह का दर्जा बढ़ाने के निर्णय के अनुरूप उच्चीकृत संयुक्त आयोग की पहली बैठक थी। इस यात्रा से दोनों पक्षों के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा विविध क्षेत्रों में सहयोग का दायरा फैलाने के लिए कड़ी प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि हुई है।

आयोग की बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने :

सकल व्यापार (साल 2924—25 में जिसका मूल्यांकन 14 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर था) की समीक्षा की तथा माल एवं सेवा में भारतीय द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा उसमें विविधता लाने के उपायों को

चिह्नित किया। उन्होंने उर्जा, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण, वित्त, प्रौद्योगिकी एवं वहनीय विकास के क्षेत्र में नए अवसरों के बूते साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का साझा लक्ष्य तय किया। आयोग की बैठक में भारत—कतर वृहद आर्थिक भाओदारी समझौते के लिए बातचीत की औपचारिक शुरूआत के वास्ते संदर्भ की शर्तें तय करने का काम जल्द निपटाने पर भी सहमति हुई।

कतर देश के अमीर की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान कतर द्वारा भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निवेश की घोषणा तथा परस्पर लाभ वाले निवेश के लिए दोनों पक्षों द्वारा नए क्षेत्रों को खोलने की प्रतिबद्धता को भी अभिस्वीकृत किया गया। डिजिटल इकॉनमी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, पर्यटन, संस्कृति एवं पर्यावरण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया।

इसके अलावा श्री गोयल ने अपने दौरे में कतर के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों तथा व्यावसायिक प्रमुखों से भी द्विपक्षीय बैठक कीं। इनमें खाद्य सुरक्षा, व्यापारिक वित्त, परियोजनाओं में साझेदारी एवं कतर के उद्यमों के लिए भारत के बुनियादी ढांचे तथा औद्योगिक क्षेत्रों निवेश के अवसरों में आपसी सहयोग एवं साझेदारी बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई।

मंत्रीवर ने भारत—कतर संयुक्त व्यवसाय परिषद (जेबीसी) की पहली बैइक को भी संबोधित किया। इसमें फिक्की, सीआईआई, एसोचैम तथा कतर चैम्बर के वरिष्ठ व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल थे। इसके बाद श्री गोयल ने कतरी बिजनेसमेन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

सम्पादकीय

जुबिन की मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाना चाहतीं हैं उनकी पत्नी

मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत को लेकर रोज नए-नए खुलासे आ रहे हैं। बता दें कि जुबिन की मौत 19 सितम्बर, 2025 को सिंगापुर में हुई थी। बता दें कि जुबिन की सिंगापुर में स्वूबा डाइविंग के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। जुबिन, श्यामकानु महंत और उनकी वंपनी की ओर से ऑगेर्नाइज इवेंट के चौथे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में जुबिन और उनके साथी स्वूबा डाइविंग के लिए गए थे। स्वूबा डाइविंग के दौरान जुबिन ने पानी में छलांग मारी और वुछ ही क्षणों में तड़पते नजर आए। बताया गया है कि जुबिन गर्ग पानी में सांस लेने के लिए हाफ रहे थे और लगभग डूबने की स्थिति में थे, उस समय सिद्धार्थ शर्मा था जो जाबो दे, जाबो दे। (जाने दो जाने दो) चिल्लाते सुना गया। ऐसा एक गवाह ने कहा है। जुबिन की मौत के बाद इस मामले की जांच चल रही है। पेस्टिवल ऑगेर्नाइजर, सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और बैंड के दो मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हालांकि इस दौरान जुबिन के बैंड के मेम्बर शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि सिंगापुर में जुबिन को जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस के पास मौजूद ऑफिशियल डाक्यूमेंट में दी गईं जानकारी के मुताबिक डिटेल्स ग्राउंड ऑफ अरेस्ट या रिमांड नोट में ज्योति ने आरोप लगाया कि जुबिन की सिंगापुर में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और नार्थ ईस्ट इंडिया पेस्टिवल के ऑगेर्नाइजर श्यामकानु महंत ने जहर दिया था। गवाह ने कहा कि जुबिन गर्ग एक ट्रेंड स्विमर थे यानी वह तैराकी में अपनी तह जानते थे और इसलिए डूबने से उनकी मौत नहीं हो सकती।

उसने आगे कहा गया है कि शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत ने सिंगर को जहर दिया था और अपनी साजिश छिपाने के लिए जानबूझकर विदेश में जगह चुनी थी। सिद्धार्थ ने उन्हें नाव के वीडियो किसी के साथ शेयर न करने का भी निर्देश दिया था।

सीआईडी का 9 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) फिलहाल सिंगापुर में गर्ग की मौत से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। सीआईडी के सूत्रों ने दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि की है। नोट में कहा गया है, गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी के बयान से पता चला है कि जुबिन गर्ग की डेथ से पहले मौत का एक्सीडेंट दिखाने की साजिश रची गईं थी। जुबिन के साथ सिंगापुर में रह रहे सिद्धार्थ शर्मा का आचरण संदिग्ध था जिसकी वजह से बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से नाव डगमगाने लगी थी। साथ ही यह भी बताया गया कि डूबते वक्त जुबिन के मुंह से और नाक से झाग निकल रहा था तो सिद्धार्थ ने जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाए उसे एसिड रिफ्लक्स बताकर टाल दिया और दूसरों को आश्वस्त किया कि चिंता की कोईं बात नहीं है। जुबिन की मौत की जांच के लिए असम सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। राजनीतिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सैंकिया की अध्यक्षता वाला यह आयोग 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उधर जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने शनिवार को अपने पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को लौटाते हुए कहा कि यह उनका निजी दस्तावेज नहीं है और जांचकर्ता ही बेहतर तय कर पाएंगे कि इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं। गरिमा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच में सिंगापुर में जुबिन की मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगा लिया जाएगा। गरिमा ने कहा कि वह बस यही चाहती हैं कि जांच सही तरीके से की जाए और सच्चाईं जल्द से जल्द सामने ने आए। जब गरिमा जुबिन के बैंड में शामिल शेखर ज्योति गोस्वामी के गायक को जहर दिए जाने के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल किया कि वह (शेखर) इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे?

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जन विश्वास, सेवा और समर्पण के 24 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य में विकास सप्ताह के जश्न का दूसरा दिन

डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और प्रधानमंत्री ने इस पूंजी को दीर्घकालिक समृद्धि के लिए देश की ताकत बनाने का संकल्प किया है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति में युवा, रोजगार और कौशल सशक्तिकरण समारोह संपन्न

658 भर्ती मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले 55 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जबकि 25 हजार से अधिक युवाओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर वितरित

उद्योगों के अनुरूप मानव संसाधन मुहैया कराने के लिए 100 से अधिक उद्योग साझेदारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कौशल, इच्छा शक्ति और जोश के जरिए पत्थर से पानी निकालने की क्षमता रखने वाली युवा शक्ति को कौशल विकास की नई राह दिखाई
- युवाओं के नवाचार को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से अनेक स्टार्टअप आत्मनिर्भर बने और गुजरात स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार 4 वर्षों से शीर्ष पर
- मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी जैसे अभियानों को अपनाने का प्रेरक आह्वान किया

गांधीनगर, 08 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साफ कहा कि विशाल युवा शक्ति (डेमोग्राफिक डिविडेंड) हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस पूंजी को दीर्घकालिक समृद्धि के लिए देश की ताकत बनाने का संकल्प किया है।

उन्होंने यह बात राज्य में 7 से 15 अक्टूबर के दौरान मनाए जा रहे विकास सप्ताह के दूसरे दिन बुधवार को गांधीनगर में आयोजित युवा रोजगार और कौशल सशक्तिकरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। इस समारोह का राज्य के 33 जिलों के आईटीआई में सीधा प्रसारण किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांधीनगर और विभिन्न मंत्रियों ने अलग-अलग जिलों में आयोजित समारोह में समग्र राज्य में आयोजित किए गए 658 भर्ती मेलों के दौरान निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले 57,502 युवाओं को सांकेतिक तौर पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।

राज्य सरकार के श्रम कौशल विभाग ने आईटीआई में ड्रॉपआउट की दर को कम करने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रोविजनल ऑफर लेटर देने की पहल की है, इसके अंतर्गत 25,000 से अधिक युवाओं को यह लेटर वितरित किए।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और श्रम एवं रोजगार तथा उद्योग मंत्री श्री बळवंतसिंह राजपूत एवं महानुभावों की उपस्थिति में उद्योगों के अनुरूप मानव संसाधन बल मुहैया कराने के लिए 100 से अधिक उद्योग साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने युवाओं को मिले इन रोजगार अवसरों को उनके घर-परिवार में दिवाली का आर्थिक उजियारा बनने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम भी करार दिया।

उन्होंने कहा कि अपने कौशल, इच्छा शक्ति और जोश (स्किल, विल और जील) के जरिए पत्थर से भी पानी निकालने की क्षमता रखने वाली युवा शक्ति को प्रधानमंत्री ने कौशल विकास की एक नई राह दिखाई है। इन 24 वर्षों में गुजरात के युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर उन्हें 'जॉब सीकर' से 'जॉब गिवर' बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में 'हर हाथ को काम' का मंत्र साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले उद्योगों को उचित मानवबल मुहैया कराने के लिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच सहयोग का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने दिया है, उसे कौशल पाठ्यक्रमों के जरिए आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कौशल्य-द स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के 12,000 से अधिक युवा ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), हेल्थ केयर और एग्रो सर्विसेज जैसे रोजगार के व्यापक अवसर वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में सफल हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात में युवा शक्ति के नवाचार को गति मिलने के कारण 12,500 से अधिक स्टार्टअप आत्मनिर्भर बने हैं और गुजरात लगातार 4 वर्षों से स्टार्टअप रैंकिंग में देश में अव्वल रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में 15 मिलियन यानी डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में गहन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है और कौशल एवं तकनीकी योग्यता के साथ जोड़ा है। ऐसे कुशल युवाओं को पीएम रोजगार अप्रेंटिसशिप के तहत उद्योगों में रोजगार भी दिए गए हैं। श्री पटेल ने इस मौके पर देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक लाख करोड़ रुपए की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पर भी प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने युवा शक्ति से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल एवं हर घर स्वदेशी जैसे अभियानों को अपनाएं।

श्रम, कौशल एवं रोजगार मंत्री श्री बळवंतसिंह राजपूत ने कहा कि पूरे राज्य में मनाए जा रहे विकास सप्ताह के दौरान राज्य के 57 हजार से अधिक युवाओं को आज रोजगार पत्र वितरित किए गए हैं, जो हम सभी के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने एक अनूठी पहल की है, जिसके अंतर्गत रोजगार मेलों के साथ-साथ युवाओं को कंपनियों के मार्गदर्शन में पढ़ाई के तुरंत बाद नौकरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

श्री राजपूत ने कहा कि आगामी समय में प्रवेश प्राप्त करने वाले 100 फीसदी युवाओं को पढ़ाई के दौरान ही स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। आज सिंगल विंडो के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के द्वारा नौकरी दी और हासिल की जा सकती है। रोजगार मेले एवं भर्तियों के अन्य माध्यमों से अनेक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात की बेरोजगारी दर केवल 1.1 फीसदी है, जो देश की 3.2 फीसदी की तुलना में काफी कम है, सरकार इस दर में और कमी लाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

श्रम, कौशल एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश भर से नागरिक गुजरात में आकर अच्छी नौकरी प्राप्त कर यहां रह रह सकते हैं। उन्होंने रोजगार प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्योगों को भी सहायता दी जाती है।

श्रम, कौशल और रोजगार विभाग के प्रधान सचिव श्री विनोद राव ने स्वागत भाषण में कहा कि आगामी समय में युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रभावी कार्य किया जाएगा। आज गांधीनगर सहित पूरे राज्य में युवाओं को नियुक्ति पत्र और प्रोविजनल ऑफर लेटर देने तथा उद्योगों के साथ एमओयू के करने के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगल वर्ष से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100 फीसदी छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक श्री नितिन सांगवान ने आभार व्यक्त किया।

इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, श्रम निदेशक श्री के.डी. लाखाणी, कौशल विकास निदेशक श्री कमलेश राठोड़ सहित श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में युवा एवं रोजगार दाता उपस्थित रहे। वहीं, पूरे राज्य से 1.5 लाख से अधिक युवा वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम से जुड़े।

विकास सप्ताह : 9 अक्टूबर, पोषण दिवसः श्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 24 वर्षों के दौरान पोषण स्तर में सुधार के लिए कई योजना अमली की गई

गुजरात की पोषण पहलों का बड़ा असरः 7 सालों में अंडरवेट बच्चे 39.7% से 17.2%, बौनेपन में 39% से 30.9%, शारीरिक दुर्बलता 25% से घटकर 6.7%

*

ड्ट पोषण सुधा, दूध संजीवनी और पूर्णा योजना का बढ़ा विस्तार, तीनों योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 20 लाख के पार

ड्ट मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना 53,065 आंगनवाड़ी सेंटर्स में लागू, हर साल 5 लाख महिला-बच्चों तक लाभ पहुँचाने का लक्ष्य

ड्ट टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील से 28 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 8 अक्टूबर, 2025: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी 24 वर्षों की जनसेवा की गाथा को उजागर करने के लिए, राज्य में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। विकास सप्ताह के अंतर्गत, 9 अक्टूबर को पोषण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछले 24 वर्षों के दौरान, गुजरात में पोषण के स्तर में सुधार के लिए कई योजनाएँ लागू की गई हैं।

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण और भोजन सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किए। आज प्रधानमंत्री के रूप में उनके 'सही पोषण देश रोशन' के मंत्र को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात की पोषण संबंधी पहलों के सकारात्मक परिणाम धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पोषण संबंधी विभिन्न पहल अमली करने के कारण राज्य ने बच्चों के अंडरवेट, बौनेपन और शारीरिक दुर्बलता जैसी चुनौतियों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है। पिछले 7 साल के आँकड़ों को देखें तो कउऊ यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवेलपमेंट सर्विसेस के तहत पोषण को लेकर गुजरात सरकार के व्यापक और सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2019 में अंडरवेट बच्चों का प्रतिशत 39.7% था, जो 2025 में घटकर 17.2% रह गया, बौनेपन 39% से 30.9% और शारीरिक दुर्बलता 25% से 6.7% तक कम हुई। यह उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ लगभग 45 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है।

हर माँ, हर बच्चा पोषितः 5 लाख लाभार्थियों तक पहुँचने का मुख्यमंत्री मातृशक्ति मिशन

माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना राज्यभर में अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म के पहले दो साल तक महिलाओं और उनके बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। राज्य के 53,065 आंगनवाड़ी सेंटर्स में महिलाओं को प्रति माह 1 लीटर मूंगफली का तेल, 1 किलो तुअर दाल और 2 किलो चने की न्यूट्रीशन किट वितरित की जाती है।

इस पहल से न केवल माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है, बल्कि उनके समग्र विकास में भी मजबूती आई है। हर साल 5 लाख महिलाएँ और बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो ऐसा मिशन है, जो मातृत्व और बचपन के शुरूआती वर्षों में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील से 28 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े

माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए गुजरात में 2017 से टेक होम राशन प्रोग्राम प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स तक राशन पहुंचाने का कार्य तीन प्रमुख डेयरी को-ऑपरेटिव्स और गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से किया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हर महीने 1 किलो राशन के चार पैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं, छह महीने से तीन साल तक के सामान्य बच्चों को बाल शक्ति आहार के सात पैकेट और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को दस पैकेट दिया जाता है।

इसके साथ ही, 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में रोजाना हॉट कुक्ड मील भी प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चों का पोषण स्तर मजबूत होने के साथ उनके शुरूआती विकास में भी मदद मिलती है। अब तक टेक होम राशन प्रोग्राम से 16.5 लाख से अधिक माताएँ और बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि हॉट कुक्ड मील का लाभ 11.6 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंचा है। इस तरह से 28 लाख से अधिक लाभार्थी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं।

पोषण सुधा, दूध संजीवनी और पूर्णाः राज्य सरकार की मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पहल

माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाने के लिए गुजरात सरकार ने लगातार महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं। पोषण सुधा योजना राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसकी शुरूआत 2017-18 में 10 जिलों से हुई थी और अब 14 आदिवासी जिलों के 106 ब्लॉकों में सक्रिय है। इस योजना के तहत हर महीने लगभग 1.2 लाख महिलाओं तक विशेष भोजन, आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम गोलियाँ और स्वास्थ्य परामर्श पहुंचाया जाता है।

इसी दिशा में दूध संजीवनी योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्ताह में पांच दिन 100 मिलीलीटर फोटीर्फाइड दूध दिया जाता है। वहीं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को हफ्ते में दो बार 200 मिलीलीटर पोषणयुक्त दूध उपलब्ध कराया जाता है। इस पहल से लगभग 9.3 लाख लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है, जिससे माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य मजबूत हुआ है। इसी तरह, पूर्णा योजना के तहत राज्य की 15 से 18 साल की करीब 10 लाख किशोरियों को हर महीने 1 किलो के चार पैकेट पोषणयुक्त आहार और हर हफ्ते आयरन-फॉलिक एसिड टैबलेट्स उपलब्ध कराई जाती हैं। इन तीनों पहलों का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करने के साथ-साथ बच्चों और किशोरियों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी है।

ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तारः भारत के सबसे बड़े डिजिटल कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए 9 नई वस्तुओं को जोड़ा गया

ई-नाम प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की संख्या बढ़कर 247 हो गई है, जिससे किसानों और व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं

(जीएनएस)।

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 09 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है। यह महत्वपूर्ण कदम किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि व्यापक कमोडिटी कवरेज और बाजार एकीकरण को और मजबूत किया जा सके।

इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत के बाजारों को जोड़ता है।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), जिसे ई-नाम पर व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदण्ड तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, ने राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय विशेषज्ञों और एसएफएसी के साथ व्यापक परामर्श के बाद तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से इन 09 नई वस्तुओं के लिए मापदण्ड विकसित किए हैं।

व्यापार योग्य मापदण्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनकी उपज की वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त हो, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो और उनकी उनकी मोलभाव शक्ति मजबूत हो। यह पहल एक पारदर्शी व्यापारिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती है।

अब तक डीएमआई ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली 238 कृषि वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं। 9 नई वस्तुओं के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 247 हो जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म की पहुंच और प्रभाव व्यापक हो जाएगा। जोड़ी गई 9 नई वस्तुएं हैंः

ग्रीन टी, चाय, अश्वगंधा की सूखी जड़ें, सरसों का तेल, लैवेंडर तेल, मेंथा ऑयल, वर्जिन जैतून का तेल, लैवेंडर के सूखे फूल, ब्रोकन राइस

व्यापार योग्य मापदण्ड वस्तुओं के लिए मानकीकृत ग्रेड या श्रेणियां प्रस्तुत करते हैं, जो कीमतों को सीधे गुणवत्ता से जोड़ते हैं और इस प्रकार किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ई-नाम पोर्टल (ल्ल्लें.ड्ड५.ल्ल) पर अब नए स्वीकृत व्यापार योग्य मापदंडों के उपलब्ध होने से यह प्लेटफॉर्म एक पारदर्शी, गुणवत्ता-संचालित बाजार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करता है। यह पहल किसानों के लिए व्यापक बाजारों तक पहुंचने, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा सुनिश्चित गुणवत्ता मानकों से लाभ उठाने के द्वार खोलती है, जिससे अंततः उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि होती है।

यह कदम पारदर्शी डिजिटल उपकरणों के साथ किसानों को सशक्त बनाने, गुणवत्ता-संचालित व्यापार को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के भारत सरकार के संकल्प को रेखांकित करता है।

एसईसीएल ने विशेष अभियान 5.0 के तहत 37 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया

सीआईएल की सहायक कंपनी ने अपशिष्ट प्रबंधन, स्क्रैप निपटान और इलेक्ट्रॉनिक एवं वास्तविक फाइल समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया

(जीएनएस)।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की मिनीरत्न सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने अपने प्रचालनगत और प्रशासनिक स्थानों पर स्वच्छता, दक्षता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना के साथ अपना महत्वाकांक्षी विशेष अभियान 5.0 आरंभ किया है।

अभियान के तहत, एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैले 203 चिन्हित स्थलों पर 37,50,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस पहल का उद्देश्य कार्यालयों, खदानों और कॉलोनियों में स्थायी हाउसकीपिंग कार्यप्रणालियां सुनिश्चित करना तथा कार्यस्थल की स्वच्छता और सौंदर्य में सुधार करना है।

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य

लगभग 37.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले 203 स्थलों की सफाई और रखरखाव।

लगभग 3,000 मीट्रिक टन स्क्रैप सामग्री का सुरक्षित निपटान।

2,000 वास्तविक फाइलों और 6,500 ई-फाइलों की विस्तृत समीक्षा।

उचित सत्यापन के बाद 2,700 ई-फाइलें बंद कर दी गईं।

कंपनी के भीतर रचनात्मकता

औरर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण।

यह अभियान प्रणालीगत फाइल समीक्षा और समापन के माध्यम से डिजिटल दस्तावेजीकरण कार्यप्रणालियों और कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन के एकीकरण पर भी जोर देता है, जो स्वच्छता और शासन में दक्षता के लिए भारत सरकार के व्यापक विजन के अनुरूप है।

पिछले वर्ष विशेष अभियान 4.0 के दौरान, एसईसीएल ने कई श्रेणियों में अपने लक्ष्यों को पार किया—सफाई स्थलों की संख्या, खाली की गई जगह और स्क्रैप निपटान के मामले में सभी कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया। कंपनी ने लोक-संपर्क और दृश्यता में भी अग्रणी स्थान अर्जित किया, कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक ट्वीट और प्रेस विज्ञप्तियां दर्ज कीं, जिससे अभियान के क्रियान्वयन और संचार में राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक स्थापित हुआ।

कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला नीलामी के अंतर्गत पांच कोयला ब्लॉकों के लिए स्वामित्व आदेश जारी किए

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय ने अपने नामित प्राधिकरण के माध्यम से आज वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के अंतर्गत 5 कोयला ब्लॉकों के लिए स्वामित्व आदेश जारी किए हैं। इन ब्लॉकों के लिए कोयला खदान विकास एवं उत्पादन समझौतों (सीएमडीपीए) पर 21 अगस्त, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे।

जिन कोयला ब्लॉकों के लिए स्वामित्व आदेश जारी किए गए हैं, वे हैं टांडसी क्क्क और टांडसी क्क्क एक्सटेंशन, सेंदुरी, टुबेद के पश्चिम, चितरपुर (संशोधित), और फूटामुरा। इनमें से चार ब्लॉक आंशिक रूप से अन्वेषित हैं और एक ब्लॉक पूर्ण रूप से अन्वेषित है। इनकी अधिकतम निर्धारित क्षमता (ढफ्छ) लगभग 3.45 मिलियन टन प्रति वर्ष (टळढअ) और लगभग 1,556.31 मिलियन टन (टळ) का भूगर्भीय भंडार है।

इन ब्लॉकों से लगभग ₹360 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने

और लगभग ₹517 करोड़ का पूंजी निवेश आने की उम्मीद है। इसके अलावा, इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4,664 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

इन निहित आदेशों के जारी होने के साथ, अब कुल 125 कोयला ब्लॉक वाणिज्यिक कोयला नीलामी के अंतर्गत निहित या आवंटित हो चुके हैं। सामूहिक रूप से इन ब्लॉकों का कुल पीआरसी लगभग 265.844 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है जिससे लगभग ₹37,463 करोड़ का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3,59,400 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए), दूरसंचार विभाग (डीओटी) और जीएसएमए ने दूरसंचार नीति, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनसीए, डीओटी और जीएसएमए ने दूरसंचार क्षेत्र में नीति विकास, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए रणनीतिक साझेदारी की

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), राष्ट्रीय संचार अकादमी (एनसीए) और जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) ने आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में माननीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

एमओयू पर औपचारिक रूप से जीएसएमए के महानिदेशक श्री विवेक बद्रीनाथ और एनसीए के महानिदेशक श्री अतुल सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जीएसएमए के मुख्य

नियामक अधिकारी (सीआरओ) श्री जॉन गिउस्टी और जीएसएमए के एपीएसी प्रमुख श्री जूलियन गोर्मन भी उपस्थित थे।

यह समझौता ज्ञापन दूरसंचार क्षेत्र में नीति विकास, अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में एनसीए और जीएसएमए के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है। इस सहयोग का उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाकर, नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं को आगे बढ़ाकर और स्थायी डिजिटल परिवर्तन के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देकर भारत के डिजिटल इंडिया विजन को मजबूत करना है।

इस साझेदारी के अंतर्गत एनसीए और जीएसएमए मिलकर काम करेंगे:

डिजिटल समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अनुसंधान, विश्लेषण और प्रशिक्षण पहल शुरू करना, डिजिटल विभाजन को पाटने, स्थिरता को बढ़ावा देने और एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के विकास का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में प्रमुख स्टॉलों का दौरा किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज यशोभूमि, नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत के डिजिटल परिवर्तन को सशक्त करने वाली प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का जीवंत प्रदर्शन देखा।

मंत्री महोदय ने अपने दौरे की शुरूआत दूरसंचार विभाग (डीओटी) मंडप के उद्घाटन से की, जहाँ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने 4जी और 5जी नेटवर्क के विस्तार, भारतनेट परियोजना की प्रगति, टेलीकॉम स्टार्टअप एक्सेलरेटर और स्वदेशी

दूरसंचार विनिर्माण एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलों पर आधारित प्रदर्शनियों को देखा । मंत्री महोदय ने देश भर में किफायती कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और मजबूत दूरसंचार अवसंरचना को सक्षम बनाने में दूरसंचार विभाग के निरंतर प्रयासों की सराहना की। मंत्री महोदय ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और नागरिक सुरक्षा को बढ़ाने में दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल और ऐप की भूमिका की सराहना की।

सी-डॉट पैवेलियन में, मंत्री महोदय ने 4जी, 5जी और उपग्रह संचार के साथ-साथ प्रारंभिक चरण की 6जी तकनीकों में स्वदेशी रूप से विकसित समाधानों का प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने वाले अनुसंधान, नवाचार और सुरक्षित दूरसंचार समाधानों को आगे बढ़ाने में सी-डॉट की भूमिका की सराहना की।

भारत नवाचार को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाकर इसका लोकतंत्रीकरण कर रहा है : डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन भारत को कनेक्टिविटी से लेकर वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जा रहा है कॉलेज छात्रावासों से लेकर अंतरिक्ष मिशनों तक भारत में नवाचार इंजन अब समावेशी हैं

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के अवसर पर "कनेक्टिविटी से आगे: भविष्य के नवाचार के इंजनों का लोकतंत्रीकरण" के विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नवाचार को एक विशिष्ट प्रयास से

जनांदोलन में बदल रहा है।

डॉ. चंद्रशेखर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत एक ऐसा नवाचार इको-सिस्टम तैयार कर रहा है जो समावेशी, सुलभ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो। उन्होंने कहा, "हम भविष्य के नवाचार के इंजनों को प्रत्येक भारतीय के लिए उपयोगी बनाकर इसका लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं।"

डॉ. चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय चिंतन में आए बदलाव को भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अटल टिंकरिंग लैब्स से लेकर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तक की पहल नवाचार को सभी के लिए सुलभ बना रही हैं। भारत की विरासत - शून्य और शतरंज - पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, "नवाचार हमारे डीएनए में है और हम इसे एक नई सदी के लिए जागृत कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने जो हासिल किया है वह व्यवस्थित है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई के प्रयोग से स्वदेशी कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार, वास्तव में असरदार प्रभाव दिखा रहे हैं: श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने मवेशियों के स्वास्थ्य की निगरानी और दालों, चावल, सूखी लाल मिर्च की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी आधारित डेयरी समाधान के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन सहित विभिन्न प्रयोगों के लिए सेंसर आधारित गंध निगरानी प्रणाली की शुरूआत की घोषणा की है।

एग्रीइनइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, परिनियोजन, प्रदर्शन और व्यावसायीकरण शामिल है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन, उन्नत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), कोलकाता द्वारा नोडल एजेंसी

के रूप में किया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योगों की एजेंसियां भाग ले रही हैं। उपरोक्त सभी पाँच प्रौद्योगिकियों का विकास और परीक्षण इस कार्यक्रम के तहत किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की मौजूदगी में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) और उत्पाद लॉन्च का विवरण इस प्रकार है:

सी-डैक (के), आईआईटी, खड़गपुर और आईसीएआर-एनडीआरआई, कल्याणी द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित डेयरी समाधान की प्रौद्योगिकी का मेसर्स हैंडहोल्डर्स ग्लोबल, भुवनेश्वर को हस्तांतरण: इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित डेयरी समाधान दो प्रौद्योगिकियों का एक पैकेज है, जिसमें मवेशी स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली (गो-पी) और मास्टिटिस डिटेक्शन (एमएएसटी-डी) शामिल हैं। गो-पी मवेशियों के लिए पहनने योग्य कॉलर-माउंटेड आईपी67 रेटेड डिवाइस है, जो कृत्रिम गभार्धान के लिए मवेशियों के 'तापमान' की स्थिति को भांपने के लिए वास्तविक समय में शारीरिक तापमान परिवर्तन की निगरानी करता है, जो मवेशी प्रजनकों के लिए एक प्रमुख जरुरत होती है।

आईआईसीए ने 'जनजातीय विकास के लिए सीएसआर उत्कृष्टता का लाभ' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का समापन किया

यह सम्मेलन समुदाय-केंद्रित सीएसआर पहलों के माध्यम से समावेशी, सहयोगात्मक और सतत विकास के आह्वान के साथ द्वितीय आईआईसीए सीएसआर दिवस का प्रतीक है

डीपीई सचिव श्री के. मोसेस चालई ने सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला; स्पष्ट उद्देश्यों, मापनयोग य लक्ष्यों का आह्वान किया और ठोस सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए

एमसीए सचिव श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी ने जनजातीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए नीति निमार्ताओं, उद्योगपतियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को एक साथ

लाने वाले एक सहयोगी मंच के निर्माण के लिए आईआईसीए की सराहना की

कारपोरेट सामाजिक दायित्व को विभिन्न गतिविधियों को धन-आधारित मार्गदर्शन पर प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय योगदान से आगे बढ़कर तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए - आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह

(जीएनएस)।

जनजातीय विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उत्कृष्टता का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का समापन सत्र 7 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा आयोजित किया गया था। इस

भारत ई-बैंक गारंटी के लिए वास्तविक समय डिजिटल दस्तावेज निष्पादन के साथ पेपरलेस शासन की ओर अग्रसर

बैंक, एनबीएफसी, पूंजी बाजार संस्थाओं और कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे 60 से अधिक संस्थानों को लाभ क्योंकि बैंक गारंटी जारी करने, नवीनीकरण और इन्वोकेशन का काम वर्तमान कुछ दिनों की जगह कुछ मिनटों में किया जा सकता है

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के एंटिटी लॉकर को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के डिजिटल डॉक्यूमेंट निष्पादन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना ताकि त्वरित, पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा दिया जा सके

डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन और निष्पादन को बढ़ाने के लिए एनईजीडी और एनईएसएल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; भारत के डिजिटल गवर्नेंस विजन में तेजी लाने और उद्यमों के लिए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य

(जीएनएस)।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा विनियमित एक सूचना उपयोगिता केंद्र, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) ने व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बढ़ाने और एकीकृत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में एनईजीडी के निदेशक श्री जेएल गुप्ता और एनईएसएल के एमडी और सीईओ श्री देबज्योति रे चौधरी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस सहयोग के माध्यम से, एनईजीडी का क्लाउड-आधारित दस्तावेज प्रबंधन प्लेटफॉर्म, एंटिटी लॉकर झ जो दस्तावेज जारी करने, भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से डिजिलॉकर पहल का एक विस्तार है झ एनईएसएल के डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (डीडीई) प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होगा। एनईएसएल का डीडीई प्लेटफॉर्म एक अग्रणी समाधान है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) सहित अनुबंधों के डिजिटल, कागज रहित और सुरक्षित निष्पादन की सुविधा प्रदान करता है, जो डिजिटल रूप में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं।

यह समझौता ज्ञापन ई-बीजी के लाभार्थियों और आवेदकों को एनईएसएल के ई-बीजी रिपॉजिटरी से सीधे अपने संबंधित एंटिटी लॉकर खातों में डिजिटल रूप से निष्पादित बैंक गारंटी प्राप्त करने और उन तक सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह एकीकरण तेज, अधिक पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा देगा, जो भारत के त्वरित डिजिटल शासन और व्यापार सुगमता के विजन में सहायता करेगा। एनईएसएल के ई-बीजी के लाभों में शामिल हैं

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 10 अक्टूबर 2025 को "सुशासन और अभिलेख 2025" पर प्रदर्शनी लगाएगा

प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) सुशासन माह के अनुसरण में 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में "सुशासन और अभिलेख 2025" नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह 10 अक्टूबर की सुबह 10:00 बजे करेंगे।

स्वच्छता और सुशासन एक समृद्ध समाज के अभिन्न अंग हैं, जो सार्वजनिक आचरण, सामाजिक अंतःक्रिया और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को आकार देते हैं। इस संबंध में प्रमुख राष्ट्रीय पहलों में से एक स्वच्छ भारत अभियान रहा है, जिसने न केवल स्वच्छता और जन स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि राष्ट्र की अभिलेखीय विरासत के संरक्षण में भी योगदान दिया है। 2021 और 2025 के बीच, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने एक व्यापक अभिलेख प्रबंधन अभियान चलाया, जिसमें 75,500 से अधिक ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान दस्तावेजों की पहचान की गई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेजा गया।

इस प्रदर्शनी में इन अभिलेखों के चयनित संग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा जो सुशासन के स्तंभों के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिलेख-संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। यह प्रदर्शनी भारत के प्रशासनिक विकास और प्रभावी शासन में दस्तावेजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

प्रदर्शनी का एक विशेष खंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार ने समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया, और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिनका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और युवा सशक्तिकरण में योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, जैसे प्रख्यात नेताओं को श्रद्धांजलि होगा।

प्रदर्शनी राष्ट्र की विकास गाथा को आकार देने में शासन और अभिलेखीय संरक्षण के बीच गतिशील संबंधों को रेखांकित करती है।

प्रदर्शनी में विभिन्न मंत्रालयों के बहुमूल्य अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे, जो भारत की शासन व्यवस्था और विकास की प्रगति को दर्शाते हैं:

राष्ट्रपति सचिवालय: मुख्य आकर्षणों में जनरल एस. एच. एफ. जे. मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने से संबंधित अभिलेख तथा प्रमुख औपचारिक दस्तावेज शामिल हैं।

भारत निर्वाचन आयोग: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरूआत और चुनाव सुधारों को प्रदर्शित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय: विजय दिवस समारोह और पंचायती राज की उन्नति से संबंधित दस्तावेज।

विद्युत मंत्रालय: टिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अन्य मंत्रालय और विभाग - जिनमें संसदीय कार्य मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि तथा न्याय मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय

इन आख्यानों के माध्यम से, यह

दिल्ली में 'ब्रीदेबल आर्ट' का उद्घाटन किया गया - यह वायु शुद्धिकरण करने वाले पौधों और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई एक अभिनव, जीवंत संरचना है, जो वायु गुणवत्ता और स्थिर जीवन से जुड़ी जागरूकता को बढ़ावा देती है

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की संयुक्त सचिव सुश्री नमिता प्रसाद ने आज रोहिणी स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में 'ब्रीथेबल आर्ट' का उद्घाटन किया। इस आर्ट की स्थापना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई थी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इसके लिए सहयोग प्रदान किया। यह पहल पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान एवं कौशल विकास (ईईएआरएसडी) योजना के पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) के तहत आयोजित 'ब्रीथ ऑफ चेंज - स्वच्छ वायु, नीला आकाश' अभियान का एक हिस्सा है।

'ब्रीदेबल आर्ट' एक नवोन्मेषी, जीवंत संरचना है—जिसे वायु शुद्धिकरण करने वाले पौधों और टिकाऊ सामग्रियों से बनाया गया है—जो वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ शहरी जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक संवादमूलक जन-सहभागिता संस्थापन के रूप में काम करेगी। क्यूआर-कोड-सक्षम शैक्षिक सामग्री के माध्यम से, आगंतुक पौधों की शारीरिक विशेषताओं और वायु को शुद्ध करने में उनकी भूमिका के बारे में जान सकते हैं। 'ब्रीदेबल

आर्ट' एक अधिक हरित, अधिक सांस लेने योग्य दिल्ली के विजन का प्रतीक है, जहां कला और प्रकृति सह-अस्तित्व में हैं और प्रत्येक नागरिक को याद दिलाते हैं कि स्थिरता एक सांस से ही आरंभ होती है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता की लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए, यह स्थापना एक प्राकृतिक समाधान प्रदान करती है और साथ ही शहरी हरित क्षेत्रों को भी समृद्ध बनाती है। इस संरचना की परिकल्पना:

छात्रों, इको-क्लबों और स्थानीय निवासियों के लिए एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करने।

आरडब्लूए, स्कूल, कॉलेज, नगर निकाय और स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक सामुदायिक पहल के रूप में कार्य करने।

नागरिक निकायों और स्थानीय समूहों के सहयोग से दीर्घकालिक रखरखाव के साथ वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट में कार्यनीतिक युक्ति के रूप में की गई है।

इस स्थापना के अपेक्षित परिणामों में पर्यावरण जागरूकता में वृद्धि, पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली को व्यापक रूप से अपनाना तथा प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से शहरी स्थानों का रूपांतरण शामिल है - जिससे दिल्ली में स्वच्छ वायु जागरूकता के लिए एक प्रमुख मॉडल की स्थापना होगी।

'ब्रीथेबल आर्ट' में उपयोग में लाये गए वायु शुद्धिकरण पौधों में एरेका पाम, बैम्बू पाम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पारिजात, पीस लिली, एरोहेड, वीपिंग फिग और ज़िगजैग प्लांट शामिल हैं। ये प्रजातियां - खासकर शुष्क सर्दियों के महीनों में जब सांस लेने में कष्ट सामान्य बात होती है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे सामान्य बाहरी प्रदूषकों को हटाने, आर्द्रता के स्तर को नियंत्रित करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जानी जाती हैं।

'ब्रीदेबल आर्ट' प्रदर्शनी टिकाऊ शहरी जीवन और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक रचनात्मक और सार्थक कदम है। कला के सौंदर्यबोध को पौधों की प्राकृतिक वायु शुद्धिकरण क्षमता के साथ जोड़कर, यह सार्वजनिक स्थानों को पारिस्थितिक संतुलन के जीवंत प्रतीकों में बदल देती है। यह अभिनव पहल दर्शाती है कि कैसे प्रकृति-आधारित, सहभागी समाधान जागरूकता को प्रेरित कर सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं और स्वच्छ वायु तथा स्वस्थ शहरों के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए

दूरदर्शी टाइगर@2047 योजना के अंतर्गत भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक प्रत्येक संभावित टाइगर लैंडस्केप को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा है: श्री भूपेंद्र यादव

जन भागीदारी वन्यजीव संरक्षण की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है - लद्दाख में हिमाल रक्षक, मध्य प्रदेश में चीता मित्र और गुजरात में वन्य प्राणी मित्र, सामुदायिक प्रबन्धन की शक्ति के प्रतीक हैं: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ऊजार्वान नेतृत्व में राष्ट्र ने न केवल अपने संरक्षण ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि यह भी परिभाषित किया है कि विकास और प्रकृति कैसे सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।"

राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) की 44वीं बैठक का नई दिल्ली में आयोजन

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के तत्वावधान में कल राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) की 44वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की सचिव एवं एनसीवीईटी की अध्यक्ष सुश्री देबाश्री मुखर्जी ने की।

इस सत्र में अधिनिर्णय करने वाली वाली संस्थाओं (एबीएस), उद्योग, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के साथ कौशल योग्यता के अनुरूप संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच पर लाया गया।

स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऑटोमोटिव, दूरसंचार, आईटी-आईटीईएस, खुदरा, रसद, पर्यावरण और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 210 कौशल योग्यताएं मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। इन योग्यताओं का उद्देश्य भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और सुगमता को बढ़ाना है।

एनएसक्यूसी राष्ट्रीय कौशल विकास इको सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि योग्यताएं एनएसक्यूएफ के अनुरूप हों, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है और यह बढ़ती जटिलता और योग्यता के स्तरों के अनुसार योग्यताओं को संरचित करता है। यह संरेखण शिक्षार्थियों के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता को सक्षम बनाते हुए सुनिश्चित करता है कि कौशल विकास उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय नियामक के रूप में, एनसीवीईटी, एनएसक्यूसी के माध्यम से एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन प्रक्रिया की देखरेख करता है। इस समिति में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य कौशल विकास मिशनों, यूजीसी, एआईसीटीई, एनएसडीसी, डीजीटी जैसी नियामक संस्थाओं और प्रमुख उद्योग संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक योग्यता की एनसीवीईटी द्वारा व्यापक और बहु-हितधारक समीक्षा की जाती है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, शिक्षाविद और संबंधित मंत्रालय शामिल होते हैं।

44वीं एनएसक्यूसी बैठक के परिणामों, विशेष रूप से 210 कौशल योग्यताओं के मूल्यांकन से भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने और राष्ट्रीय तथा वैश्विक उद्योग की मांगों को पूरा करने में सक्षम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की आशा है।

मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की पावन नगरी श्री अयोध्या धाम में आज माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती Nirmala Sitharaman जी के साथ # यूपीसीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी बृहस्पति कुंड स्थल पर दक्षिण भारत के प्रमुख संतों की प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दक्षिण भारत में भगवान राम को अपना सबसे विश्वसनीय सखा अगर कोई प्राप्त हुआ था तो वे श्री हनुमान जी थे। 'अयोध्या धाम' में सुग्रीव जी का किला भी है, माता शबरी की भी प्रतिमा स्थापित हो रही है और निषादराज को भी सम्मान दिया जा रहा है

श्री जयंत चौधरी ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए नीति आयोग के एआई रोडमैप का अनावरण किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने आज डिलॉयट के साथ साझेदारी में विकसित नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब रिपोर्ट "समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई'का शुभारंभ किया।

इस रिपोर्ट के शुभारंभ समारोह में श्रीमती देबश्री मुखर्जी (सचिव, कौशल विकास मंत्रालय), सुश्री वंदना गुनार्नी (सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), श्री एस. कृष्णन (सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और सीईओ, नीति आयोग और सुश्री देबजानी घोष (विशिष्ट फेलो, नीति

आयोग व फ्रंटियर टेक हब की प्रमुख वास्तुकार) उपस्थित थे। इन सभी की उपस्थिति सरकार के कौशल विकास तंत्र को आधुनिक आईटीआई, सुदृढ़ उद्योग संबंध और तकनीक-आधारित कौशल विकास पहलों के जरिए बदलाव करने में सहयोगी दृष्टिकोण को दशार्ती हैं।

यह रिपोर्ट पहली बार किसी प्रणालीबद्ध अध्ययन के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रंटियर तकनीकों के माध्यम से भारत के 490 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों के जीवन और आजीविका में बदलाव की संभावनाओं का विश्लेषण करती है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

जहां वैश्विक चर्चा अधिकतर व्हाइट-कॉलर नौकरियों और औपचारिक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रही है, यह अध्ययन अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारत की जीडीपी में लगभग आधा योगदान देता है, लेकिन औपचारिक सुरक्षा, अवसर और उत्पादकता प्रणालियों से वंचित है।

श्री चौधरी ने कहा कि यह रिपोर्ट अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में समावेशन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई के इस्तेमाल का रोडमैप देती है, जो भारत के 2047 में विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

निफ्टम-के ने अपना छठा दीक्षांत समारोह और 13वां स्थापना दिवस मनाया, खाद्य उद्योगपतियों की अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित किया

(जीएनएस)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टम-के), कुंडली ने अपना 6ठा दीक्षांत समारोह और 13वां स्थापना दिवस भव्यता, शैक्षणिक गौरव और नवाचार की भावना के साथ मनाया।

दीक्षांत समारोह में केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री देवेश देवल और बीकानेरवाला के प्रबंध निदेशक श्री श्याम सुंदर अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। निफ्टेम-के के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के अध्यक्ष प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने समारोह

की अध्यक्षता की।

दीक्षांत समारोह में कुल 262 विद्यार्थियों (126 बी.टेक, 92 एम.टेक, 27 एमबीए और 17 पीएचडी) को डिग्री प्रदान की गई जबकि सात मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रो. अजय कुमार सूद ने देश के खाद्य प्रसंस्करण परितंत्र को आकार देने में निफ्टेम-के की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में भी "भोजन सबसे बुनियादी मानवीय जरूरत बना हुआ है।" यह बताते हुए कि दुनिया भर में 2.6 अरब लोग स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते, उन्होंने युवा प्रौद्योगिकीविदों से आग्रह किया कि वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और करुणा का संयोजन करके सभी के लिए नवीन, पौष्टिक और किफायती खाद्य समाधान विकसित करें। उन्होंने यह भी कहा कि निफ्टेम को नवाचारों और गहन तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से देश में खाद्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्होंने संस्थान के लिए अनुसंधान के कुछ आगामी क्षेत्रों का भी सुझाव दिया।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और आईआईटी पलक्कड़, केरल के बीच पीएम विकास योजना के तहत कौशल विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

(जीएनएस)।

भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 8 अक्टूबर 2025 को केरल के पलक्कड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पलक्कड़ के साथ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के तहत एक कौशल विकास की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अल्पसंख्यक कार्य तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री श्री जॉर्ज कुरियन इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से संबंधित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री विकास योजना के उद्देश्यों के अनुरूप, केरल के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को उभरते क्षेत्रों में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी कौशल से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है।

इस सहयोग के तहत, आईआईटी पलक्कड़ अल्पसंख्यक समुदायों पर केन्द्रित 400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने हेतु मंत्रालय का कार्यान्वयन भागीदार होगा। कुल 150 प्रशिक्षुओं को जूनियर चिप डिजाइनर तथा अन्य 150 प्रशिक्षुओं को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि शेष 100 प्रशिक्षुओं को

जूनियर इंजीनियर (ड्रोन अनुसंधान एवं विकास) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रशिक्षण का पूरा खर्च अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। आईआईटी पलक्कड़ कार्यान्वयन संस्थान के रूप में कार्य करेगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलेगा और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार से संबंधित अवसरों के लिए प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य सचिव डॉ. चन्द्र शेखर कुमार, आईआईटी पलक्कड़ के निदेशक प्रोफेसर ए. शेषाद्रि शेखर और मंत्रालय एवं आईआईटी के अधिकारी, संकाय सदस्य, छात्र और पीएम विकास के तहत सहायता पाने के आकांक्षी लोग उपस्थित थे।

राज्यमंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री विकास योजना भारत सरकार की एक ऐसी प्रमुख पहल है जो कौशल विकास और उद्यमिता के प्रोत्साहन के जरिए अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि ऐसी पहल रोजगार क्षमता को बढ़ाती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है और स्थायी आजीविका के सृजन में योगदान देती है।

आईआईटी पलक्कड़, जिसे प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रतिभा को निखारने पर जोर देने वाले राष्ट्रीय महत्व के एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में जाना जाता है, में इस परियोजना के कार्यान्वयन से केरल के अल्पसंख्यक समुदायों के बीच क्षमता निर्माण और कौशल विकास को उल्लेखनीय रूप से मजबूती मिलने की उम्मीद है8

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025' के मसौदे पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की

(जीएनएस)।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति – श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया है। यह मसौदा नीति, विकासशील भारत @2047 की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप एक निष्पक्ष समावेशी और भविष्योन्मुख कार्य-विश्व के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

श्रम धर्म-काम की गरिमा और नैतिक मूल्य की भारतीय सभ्यतागत भावना पर आधारित यह नीति एक ऐसे श्रम संस्कृति की परिकल्पना करती है जो प्रत्येक श्रमिक के लिए सुरक्षा, उत्पादकता और भागीदारी सुनिश्चित करे। इसका उद्देश्य एक संतुलित ढांचा तैयार करती है जो श्रमिकों के हितों को बढ़ावा देते हुए उद्यमों को विकसित होने और स्थायी आजीविका उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

श्रम शक्ति नीति 2025 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) को एक सक्रिय रोजगार सुविधा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगी जो विश्वसनीय, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों के माध्यम से श्रमिकों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफॉर्म, रोजगार के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करेगा, जिससे पारदर्शी और समावेशी नौकरी अवसर, प्रमाणपत्र सत्यापन और कौशल संरेखण संभव होगा। ओपन एपीआई, बहुभाषी पहुंच और एआई-संचालित नवाचार के माध्यम से, एनसीएस-डीपीआई, टियर-2 और टियर-3 शहरों, ग्रामीण जिलों और एमएसएमई समूहों में प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगा जिससे रोजगार सुविधा एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक सुविधा बन जाएगी।

यह नीति सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं युवा सशक्तिकरण तथा हरित एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। इसका उद्देश्य एक लचीला और निरंतर कुशल कार्यबल का निर्माण करना है जो उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तनों और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की मांगों को पूरा करने में सक्षम हो। ईपीएफओ, ईएसआईसी, ई-श्रम और एनसीएस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय डेटाबेस को एक एकीकृत श्रम स्टैक में एकीकृत करते हुए यह नीति एक समावेशी और अंतर-संचालनीय डिजिटल संस्कृति की कल्पना करती है जो आजीवन शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आय सुरक्षा का समर्थन करता है।

मसौदा नीति व्यापक हितधारक परामर्शों को प्रतिबिंबित करती है और सहकारी संघवाद, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और डिजिटल पारदर्शिता पर जोर देती है। यह केंद्र, राज्यों, उद्योग और सामाजिक भागीदारों के बीच समन्वित कार्रवाई के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ व्यापक और समान रूप से साझा किए जाएं।

राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति-श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) और राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। हितधारकों, संस्थानों और आम जनता से 27 अक्टूबर 2025 तक अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित है।

पिछले एक दशक में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की परिवर्तनकारी उपलब्धियों को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा मान्यता दी गई है: डॉ. मनसुख मांडविया

आईएसएसए में भारत का बढ़ा हुआ वोट शेयर वैश्विक सामाजिक सुरक्षा संवाद को आकार देने में देश के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को दशार्ता है- डॉ. मांडविया

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवर पिछले दशक में वर्ष 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64 प्रतिशत हो गया, जो तीन गुना से अधिक वृद्धि को दशार्ता है

असंगठित श्रमिकों के दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस में से एक ई-श्रम पोर्टल की आईएसएसए द्वारा सराहना

भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कुआलालम्पुर में प्रतिष्ठित आईएसएसए पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया

(जीएनएस)।

इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) ने भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और अपने नागरिकों के लिए समावेशी कल्याण सुनिश्चित करने में देश के अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता देता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज मीडिया से बातचीत में इस बात पर प्रकाश डाला। पिछले सप्ताह मलेशिया के कुआलालम्पुर में प्रदान किया

गया आईएसएसए पुरस्कार भारत सरकार की ओर से डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्रहण किया।

डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पुरस्कार पिछले एक दशक में मोदी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों का प्रमाण है। उन्होंने आईएसएसए महासभा में भारत के वोट शेयर में 30 की वृद्धि पर भी जोर दिया, जो किसी भी सदस्य देश के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा है। डॉ. मांडविया ने कहा, "यह उपलब्धि वैश्विक सामाजिक सुरक्षा संवाद और सहयोग को आकार देने में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को दशार्ती है।"

आईएसएसए पुरस्कार एक प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान है, जो हर तीन वर्ष में एक बार विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच पर प्रदान किया जाता है । इस सम्मान को प्राप्त करने वाले देशों में ब्राजील (2013), चीन (2016), रवांडा (2019) और आइसलैंड (2022) शामिल हैं। वर्ष 1927 में स्थापित, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) में 158 देशों के 330 से अधिक सदस्य संगठन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा रेखांकित किया गया है कि यह कवरेज वर्ष 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 94 करोड़ (940 मिलियन) से अधिक नागरिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने वाला एक प्रमुख सुधार चार वर्ष पहले शुरू किया गया ई-श्रम पोर्टल है, जिसने 31 करोड़ (310 मिलियन) से अधिक असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी सेवाओं से जोड़ा है।

आईएसएसए पुरस्कार 2025 एक समावेशी, न्यायसंगत और प्रौद्योगिकी-संचालित सामाजिक सुरक्षा इको-सिस्टम के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के तहत सुरक्षित रहे, चाहे वह संगठित या असंगठित में से कोई भी क्यो न हो।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 'संकट के शहरी समाधान' विषय पर विश्व पयार्वास दिवस 2025 मनाया

हर शहर को सुरक्षित और समावेशी बनाएं : माननीय राज्य मंत्री

(जीएनएस)।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 'संकट के शहरी समाधान' विषय पर विश्व पयार्वास दिवस 2025 मनाया। इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे शहर लचीले, समावेशी और टिकाऊ बनने के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और साथ ही जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और शहरीकरण जैसी चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू थे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला, मंत्रालय में अपर सचिव श्री सतिंदर पाल सिंह, सभी के लिए आवास/आवास प्रभाग के संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, यूएन- इंडिया श्री शोम्बी शार्प, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और स्वायत्त संगठनों के सीएमडी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, हुडको, एनएचबी आदि ने भी भाग लिया।

मुख्य भाषण देते हुए, माननीय

राज्य मंत्री ने सतत शहरीकरण और देश की विकास यात्रा से इसके जुड़ाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर शहर को सम्मानजनक और लोगों के लिए अवसर-योग्य बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। माननीय राज्य मंत्री ने आगे कहा कि विश्व पयार्वास दिवस 2025 का विषय केवल एक और कैलेंडर वर्ष नहीं है, बल्कि ऐसे शहरों के निर्माण के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है जो लचीले, समावेशी, टिकाऊ हों और साथ ही, संकट का सामना करने और मजबूती से उभरने के लिए तैयार हों। उन्होंने स्पष्ट रूप से शहरों को सुरक्षित, लचीले, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया।

माननीय राज्य मंत्री ने कहा, "यदि हम लचीलेपन में समझदारी से निवेश करते हैं, स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाते हैं और सार्वजनिक-निजी-जन भागीदारी की क्षमता का दोहन करते हैं, तो हमारे शहर न केवल संकट का सामना करने में सक्षम होंगे, ल्कि विकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में भी उभरेंगे।"

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि शहरी संकट के प्रति नीतिगत प्रतिक्रिया में शहरों के बुनियादी ढांचे, सामाजिक प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं को अधिक लचीला और अनुकूलनीय बनाकर उन्हें मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि शहरों के सामने कई चुनौतियाँ हैं, फिर भी वे परिवर्तनकारी कार्रवाई के अनूठे अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे विकास और लचीलेपन का एक सकारात्मक चक्र बनता है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने कहा, "भारत का दृष्टिकोण इन चुनौतियों को भविष्य के विकास और समृद्धि की नींव में बदलने के स्पष्ट दृष्टिकोण से निर्देशित है।"

पीएमएवाई- शहरी, अमृत, पीएम स्वनिधि और स्वच्छ भारत मिशन जैसी मंत्रालय की विभिन्न प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने आगे कहा कि इन योजनाओं की अवधारणा कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई है। ये सभी मिलकर एकीकृत और बहुआयामी रणनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे सामाजिक समावेशन, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।